

गांधी मैदान पहुंच सीएम ने दी ईद की बधाई

संवाददाता ■ पटना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईद पर प्रदेशवासियों को मुबारकबाद दी है. साथ ही प्रदेश की सुख-समृद्धि, प्रगति, उन्नति व विकास की कामना की है. उन्होंने शुक्रवार को गांधी मैदान, फुलवारीशरीफ के खानकाह मुजीबिया व इमारत-ए-शरिया पहुंच कर मुसलिम भाइयों से मुलाकात की और ईद की बधाई दी. गांधी मैदान में इमाम इदैन हजरत मौलाना ख्वाजा अब्दुलबारी से मुलाकात कर सीएम ने मोसाफा किया. इदैन कमेटी के सदर महमूत आलम ने सीएम को टोपी पहना कर साफा पेश किया. बच्चों के साथ सीएम ने सेवई का लुफ उठाया. फुलवारीशरीफ के खानकाह मुजीबिया में पीर साहब सजादानशीं हजरत मौलाना सैयद शाह हयातुल्लाह से मुलाकात कर सीएम ने ईद की मुबारकबाद दी. इमारत-ए-



गांधी मैदान में लोगों को ईद की बधाई देते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार.

शरिया में अमीर-ए-शरीयत हजरत मौलाना निजामुद्दीन शाह व सचिव मौलाना अनिसुर्रहमान कासमी से मुलाकात कर ईद की मुबारकबाद दी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि ईद समता, आपसी भाईचारा, पारस्परिक प्रेम व सांप्रदायिक सोहार्द का स्रोतार है. छोटे-बड़े, गरीब-अमीर, ऊंच-नीच, सभी



पटना सिटी के मीतनघाट खानकाह में सेवई खाते राजद प्रमुख लालू प्रसाद.

फर्क मिट जाते हैं. जुम्मा के दिन ईद का होना खुशी की बात है. मौके पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष

नौशाद अहमद, सीएम के प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह, सचिव अतिश चंद्रा व संजय कुमार सिंह, ओएसडी गोपाल सिंह भी मौजूद थे.

आपसी भाईचारे का पर्व है ईद : लालू

पटना ■ राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने कहा कि ईद भाईचारे का पर्व है. यह भाईचारा, शांति व सद्भाव का संदेश देती है. उन्होंने फुलवारीशरीफ के खानकाह मुजीबिया, इमारत-ए-शरिया, पटना सिटी के खानकाह इमादिया, दरगाह-ए-इश्क तकिशारीफ, खानकाह मोनमिया मितनघाट, मस्जिदा इस्लामुल मुसलमिन मीर शिकार टोली में मौलाना अब्दुय शमी जाफरी, सुलताननजो व सखीबाग में लोगों से गले मिल कर ईद की मुबारकबाद दी. उनके साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी, रामकुपाल यादव, अनवर अहमद, मो जावेद, कोर अहमद, सलाउद्दीन मंसूरी, निगम पार्श्व धर्मेन्द्र गुप्ता भी मौजूद थे.

ईद मुबारक



लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान ने ईद के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि ईद में सभी राग-द्वेष भुला कर गले मिलते हैं. पार्टी के पटना महानगर अध्यक्ष मो कर्णाल परवेज के निवास पर जाकर उन्होंने ईद मिलन समारोह में भाग लिया. मौके पर लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराम पासवान, पूर्व सांसद डॉ एजाज अली, पूर्व मंत्री शाहजहां अहमद, प्रदेश महासचिव महताब आलम, मीडिया प्रभारी ललन कुमार चंद्रवंशी, डॉ सत्यानंद शर्मा, विष्णु पासवान, दीनानाथ क्रांति, राजेंद्र विश्वकर्मा, उपेंद्र यादव, राजेश गुंजन, अनिल कुमार आदि मौजूद थे.

■ सिपाहियों की नियुक्ति से कमी होगी दूर

अब बहाल नहीं होंगे सैप जवान

कौशलेंद्र मिश्र ■ पटना

'भागिरे चितकबरा अएलो'. सहरसा में सैप जवानों को देखते ही अपराधी भागते हुए चिल्लाते थे. वर्ष 2006 के अप्रैल-मई में पंचायत चुनाव का वक्त था. सहरसा के तत्कालीन एसीए जावेद अख्तर ने सैप जवानों से कहा था, 'स्थानीय भाषा का प्रयोग न करें. अपराधी आपसे और दूर भागेंगे.' लेकिन, सैप जवानों की इनक धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है. अब, तो पुलिस मुख्यालय के आलाधिकारी भी स्वीकारते हैं कि सैप जवानों की जरूरत नहीं है. इनकी जगह नियुक्त होनेवाले नये पुलिसकर्मियों को तैनात किया जायेगा. इधर, सैप जवान मनोज कुमार पांडे कहते हैं, भले ही सरकार हमें हटा दे, लेकिन आरोप लगा कर नहीं, सम्मानपूर्वक विदा करे. जो जवान गलती करते हैं, उन्हें जरूर हटा दिया जाये.

दूसरे राज्यों ने बिहार की पहल को अनयाया : झारखंड व ओडिशा सहित दूसरे राज्यों ने बिहार में सेवानिवृत्त फौजियों को पुलिस बल में शामिल कर संगठित अपराध को नियंत्रित करने व नक्सली वारदातों पर लामा लगाने की दिशा में पहल की थी. इन राज्यों में सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर को सैप की कमान सौंपी गयी है. बिहार में वर्ष 2006 में 1900 सैप जवानों की नियुक्ति संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए की गयी थी, तब से उनकी संविदा को प्रति वर्ष आगे बढ़ाया जाता रहा. 2010 में अंतिम रूप से सैप में बहाली की गयी. सैप में प्रारंभ में दूसरे राज्यों के सेवानिवृत्त फौजियों ने भी शामिल होने में रुचि दिखायी, लेकिन धीरे-धीरे उनका सम्मोहन टूटने लगा.

एसटीएफ को नक्सल क्षेत्रों में लगाया जायेगा : स्पेशल टास्क फोर्स को नक्सल क्षेत्रों में सीआरपीएफ के साथ तैनात किया जायेगा. इसके लिए एसटीएफ को चीता इकाई को योग्य बनाने का प्रस्ताव है. 25 अतिरिक्त चीता कर्मीयों तैयार की जानी हैं, जिनमें नवनि्युक्त पुलिसकर्मियों को शामिल किया जायेगा. एसटीएफ के विशेष प्रशिक्षण के लिए वैशाली में ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है. इसके लिए भूमि का चयन व भवन निर्माण की तैयारी पूरी कर ली गयी है.

सैप जवानों की स्थिति
वर्तमान संख्या : 7000
जवानों का वेतन : 12 हजार
अवकाश : साल में 20 दिन
वर्तदी भता : 2600 रुपये
पुलिसकर्मियों की स्थिति
बिहार में पुलिस बल : 56 हजार
नवनि्युक्त सिपाही का वेतन : 15 हजार
वर्तदी भता : 4600 रुपये
अवकाश : राज्यकर्मियों की भांति

पुलिसकर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया दुर्गापूजा बाद

सैप जवानों की जगह नये पुलिसकर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया दुर्गापूजा के बाद शुरू होगी. राज्य पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर गृह विशेष विभाग द्वारा पुलिसकर्मियों की नियुक्ति को लेकर तैयारी शुरू कर दी गयी है. कैडंबरी चरण पर्षद (सिपाही भरती) के माध्यम से सिपाही के पद पर नियुक्ति होगी. हाल ही में पूर्व की रिक्ति के आधार पर पर्षद भरती द्वारा 7606 पदों पर सिपाही की नियुक्ति की कार्यवाही पूरी की गयी है. सूबे में राष्ट्रीय ओसत को आधार बना कर 42 हजार पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की जानी है. इसे कैबिनेट की पहले ही सहमति मिल चुकी है.

नवनि्युक्त पुलिसकर्मियों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण : पुलिस मुख्यालय ने एक ओर जहां 40 वर्ष से अधिक उम्र के बिहार राज्य पुलिस-बीएसपी के पुलिसकर्मियों को जिला पुलिस बल में तैनात करने की कार्यवाही शुरू कर दी है, वहीं जिला पुलिस बल से 40 वर्ष से कम उम्र के पुलिसकर्मियों को बीएसपी में तैनात कर उन्हें सीधी कार्यवाही के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा. इसके साथ ही, नवनि्युक्त पुलिसकर्मियों को विशेष रूप से नक्सली क्षेत्रों में कार्यवाही किये जाने को लेकर प्रशिक्षण करने की योजना है.

राघोपुर में युद्ध स्तर पर चले राहत कार्य

पटना ■ लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान ने वैशाली जिले के राघोपुर के बाढ़पीड़ितों के बीच युद्धस्तर पर राहत व बचाव कार्य चलाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि राघोपुर प्रखंड के चकसिंगार, रामपुर व जोरावनपुर सहित दर्जनों गांवों के एक हजार से अधिक घर बाढ़ से घिरे हैं. करीब छह सौ घर बह गये हैं. सात लोगों की मौत हो चुकी है. सरकार के स्तर पर अब तक कोई सार्थक प्रयास नहीं किया जा सका है. पर्याप्त संख्या में नाव भी नहीं हैं. उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने व जिनका घर नदी में बह गया है, उन्हें जमीन खरीद कर घर बनवाने की मांग की है. शनिवार को वे संसदीय बोर्ड में अध्यक्ष चिराम पासवान व राष्ट्रीय महासचिव सत्यानंद शर्मा के साथ बाढ़पीड़ितों के बीच जायेंगे.

पूर्व मंत्री अनूप लाल नहीं रहे

संवाददाता ■ पटना

पूर्व मंत्री अनूप लाल यादव का शुक्रवार को सुपौल में निधन हो गया. 1967 में पहली बार विधायक बने श्री यादव 1977 में बनी कर्पुरी ठाकुर की सरकार में पथ निर्माण मंत्री रहे थे. बाद में वे सहरसा से सांसद भी हुए. 1990 में जब लालू प्रसाद की सरकार बनी, तो उन्हें मंत्री पद का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया. उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना प्रकट की है. अपने संदेश में उन्होंने कहा कि श्री यादव प्रख्यत समाजसेवी व प्रसिद्ध राजनेता थे. उनके निधन से न केवल सामाजिक, बल्कि राजनीति के क्षेत्र में भी अपूरणीय क्षति हुई है. सीएम ने उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ करना की घोषणा की है. वहीं, राजद प्रमुख लालू प्रसाद व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि वे समाजवादी विचारधारा के नेता थे. उनके निधन से समाज व राज्य को अपूरणीय क्षति हुई है. लोजपा के राष्ट्रीय

- कर्पुरी ठाकुर की सरकार में थे पथ निर्माण मंत्री
- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व लालू प्रसाद ने भी जताया शोक

अध्यक्ष रामविलास पासवान ने कहा कि अनूप लाल यादव ने हमेशा गरीब-गुरुकों की राजनीति की. वे समाज के वंचित तबकों के लिए भलाई के लिए आजीवन संघर्षरत रहे. विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता नंद किशोर यादव ने कहा कि समाजवादी विचारधारा से ओत-प्रोत अनूप बाबू मिथिलांचल व सीमांचल के लोकप्रिय नेता थे. उनके निधन से अपूरणीय क्षति हुई है.

इन्होंने भी जताया शोक : बिहार विधानसभा के अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, पूर्व मंत्री गजेंद्र प्रसाद हिमांशु, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष डॉ रामचंद्र पूर्वे, सांसद रामकुपाल यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, प्रो गुलाम गौस, सम्राट चौधरी, इलियास हुसैन, अशोक कुमार सिंह, निरतंजना गणन, रणधीर यादव, चंदेश्वर प्रसाद सिंह, रामनाथ ठाकुर, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस, सूर्य नारायण यादव, डॉ सत्यानंद शर्मा, ललन कुमार चंद्रवंशी, विष्णु पासवान, रोहित कुमार सिंह, दीनानाथ क्रांति, उपेंद्र यादव, अनिल पासवान, मनीष यादव आदि.

भीम सिंह को मंत्रिमंडल से हटाएं : लालू

संवाददाता ■ पटना

राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने कहा कि ग्रामीण कार्य मंत्री डॉ भीम सिंह ने अपने बयान से शहीदों का अपमान किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे मंत्री की तत्काल बाहर करें. शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली में रहते हुए भी शहीद जवानों को देखने नहीं गये. पटना एम्पराट पर अपने तो नहीं ही आये, उनके मंत्रिमंडल का एक भी मंत्री वहां नहीं गया. जब कारगिल युद्ध हुआ था, उस समय में उस समय एम्पराट पर शहीदों के पथिव्य शरीर को क्या लगाता था. बिहार की जनता ने उस समय सोना-चांदी व पैसा तक चंदा में दिया था, जिसे सेना के दिल्ली स्थित मुख्यालय में जमा करया था. मैं और राबड़ी देवी ने कश्मीर करण घायल सैनिकों से अस्पताल में जाकर मुलाकात की थी.

शतयात्रा में किसी मंत्री ने नहीं लिया हिस्सा : भाजपा

संवाददाता ■ पटना

राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने कहा कि ग्रामीण कार्य मंत्री डॉ भीम सिंह ने अपने बयान से शहीदों का अपमान किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे मंत्री की तत्काल बाहर करें. शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली में रहते हुए भी शहीद जवानों को देखने नहीं गये. पटना एम्पराट पर अपने तो नहीं ही आये, उनके मंत्रिमंडल का एक भी मंत्री वहां नहीं गया. जब कारगिल युद्ध हुआ था, उस समय में उस समय एम्पराट पर शहीदों के पथिव्य शरीर को क्या लगाता था. बिहार की जनता ने उस समय सोना-चांदी व पैसा तक चंदा में दिया था, जिसे सेना के दिल्ली स्थित मुख्यालय में जमा करया था. मैं और राबड़ी देवी ने कश्मीर करण घायल सैनिकों से अस्पताल में जाकर मुलाकात की थी.

शतयात्रा में किसी मंत्री ने नहीं लिया हिस्सा : भाजपा

पटना ■ विधायक व भाजपा के मुख्य पवक्ता विनोद नारायण झा ने कहा कि शहीद सैनिकों के अंतिम संस्कार में भोजपुर, बिहटा व छपरा में चार मंत्रियों के शामिल होने का मुख्यमंत्री और जदयू का दावा सफेक झूठ है. सरकार के पास वीडियो फुटेज उपलब्ध है. मुख्यमंत्री इसे प्रमाणित करें या गलतबयानों के लिए जनता से माफ़ी मांगें. उन्होंने कहा कि छपरा में शहीद प्रेमनाथ व रघुनंदन प्रसाद की शतयात्रा व अंतिम संस्कार में किसी मंत्री ने भाग नहीं लिया, जबकि सीएम कह रहे हैं कि वहां अवधेश कुशवाहा व नरेंद्र सिंह गये थे. सच तो यह है कि जनताकोश के मय से दोनों मंत्री शतयात्रा व अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए. पटना एयरपोर्ट से मात्र एक ही दूरी पर मंत्रियों के आवास हैं, इसके बावजूद कोई नहीं पहुंचा. मंत्री भीम सिंह द्वारा आपतिजनक टिप्पणी के बाद माफ़ी मांगने को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री यदि सचमुच दुखी हैं, तो उन्हें अविर्बल बरख़ास्त करें.

माफ़ी मांगने पर भी निशाना बनाना राजनीति से प्रेरित

पटना ■ शहीदों के खिलाफ अमर्वादित टिप्पणी के बाद माफ़ी मांगने के बावजूद डॉ भीम सिंह के खिलाफ हो रही बयानबाजी को जदयू ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. पूर्व विधायक अजय पासवान व पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगने के बाद मानले का पटाक्षेप हो जाना चाहेिए था. इसके बावजूद मंत्री से इस्तीफा मांगना राजनीति का हिस्सा है. अतिपिछड़ा वर्ग के नेता होने के कारण विपक्षी दलों को मंत्री पद नहीं रहे हैं. चूँकि, वह विपक्ष को करारा जवाब देने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए एन-केन-पकारेण उन्हें बढवाना करने की साजिश रची जा रही है.

हमेशा याद रहेगी शहादत : सिंह

बिहार राज्य योजना पर्षद उपाध्यक्ष हरि किशोर सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पूछ सेंटर में पाकिस्तानी हमले में पांच भारतीय जवानों

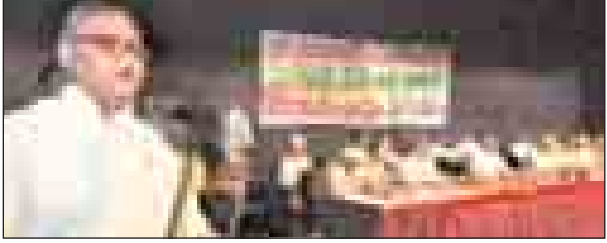
की शहादत पूरे देश को हमेशा याद रहेगी. इस पर गर्व भी है और दुख भी. ईश्वर से प्रार्थना है कि दुख की इस घड़ी में शहीद जवानों के परिवारों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें.

उन्होंने कहा कि केरल में रहने के कारण शहीदों की अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो पाने की असमर्थता पर अपसोस है, लेकिन श्राद्धकर्म में शामिल होकर श्राद्धसुभन अर्पित करेंगे.

हक के लिए संगठित रहें आदिवासी : भीम सिंह

संवाददाता ■ पटना

बिहार आदिवासी अधिकार फोरम की ओर से कालिदास रंगालय में आदिवासी अधिकार सम्मेलन हुआ. उद्घाटन ग्रामीण कार्य मंत्री डॉ भीम सिंह ने किया.



आदिवासी अधिकार सम्मेलन को संबोधित करते ग्रामीण कार्य मंत्री डॉ भीम सिंह.

उन्होंने कहा कि बिहार का आदिवासी समाज अपने हक के लिए अन्य राज्यों की तुलना में अधिक संगठित है, यह सराहनीय है. आदिवासियों पर अत्याचार न हो. इसके सरकार ने राज्य

अनुसूचित जनजाति आयोग गठित किया है. आदिवासी देश के मूलवासी कहलाते हैं. इसलिए उनकी समस्याओं के समाधान में प्राथमिकता मिलनी

चाहिए. जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि बिहार में विनम्र बने रहकर आदिवासियों की संगठित लड़ाई से आदिवासी राजनीति

को दिशा मिल गयी है. आदिवासी परिवार के बच्चों को स्कूल में भेजने की गारंटी के लिए भी आदिवासी अधिकार फोरम को पहल करनी चाहिए. फोरम के संरक्षक डॉ प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि सहकारी संगठन पैक्स में आदिवासी आरक्षण 75 प्रतिशत उपस्थिति वाले सभी छात्रों को छात्रवृत्ति एवं आदिवासी विकास के लिए वजट में स्वतंत्र कोड लॉक किया जाना सराहनीय है. मौके पर विधान पार्श्व रुदल राय, झूलन गौड, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य प्रसाद सरकार उपस्थित थे. अध्यक्षता डॉ सुजाता सुम्बई ने की.

बीपीएल सूची से बाहर के एससी एसटी को मिलेगा इंदिरा आवास

संवाददाता ■ पटना

पटना ■ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के योग्य परिवारों का नाम फिर से बीपीएल सूची में शामिल किया जायेगा. ऐसे परिवारों का नाम उन पंचायतों की बीपीएल सूची में जोड़ा जायेगा, जहां पर इंदिरा आवास की मूल प्रतीक्षा सूची के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी लाभार्थियों को आवास का लाभ मिल चुका है.

इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग ने सभी उप विकास आयुक्तों को अप्रैल में ही निर्देश दिया था, लेकिन

अभी तक किसी ने विभाग को ऐसे परिवारों की सूची नहीं भेजी. विभाग ने अब सूची भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त निर्धारित कर दी है. विभाग द्वारा निर्धारित फॉर्मट भेजा गया है, जिसमें रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है.

इसमें प्रखंड का नाम, आवेदनों की संख्या, विशेष अभियान में शामिल बीपीएल परिवारों की संख्या, प्रतीक्षा सूची में शामिल परिवारों की संख्या व कितने परिवारों को इंदिरा आवास की स्वीकृति दी गयी आदि हैं.

छूटे शिक्षक अभ्यर्थियों को एक और मौका

पटना ■ राज्य सरकार जीव विज्ञान, विज्ञान व गणित विषयों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मेधासूची में आये आवेदकों को काउंसेलिंग का एक और मौका दे सकती है. कई आवेदक काउंसेलिंग में उपस्थित नहीं हुए थे. इसके लिए शिक्षा विभाग में मंथन जारी है. 12 अगस्त को पटना हाइकोर्ट में सरकार को शिक्षकों की नियुक्ति के मामले की रिपोर्ट करनी है. कोर्ट ने इजाजत दी, तो विभाग आवेदकों को एक और मौका दे सकता है. कोर्ट के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने तीनों विषयों के लिए पांच अगस्त को काउंसेलिंग की तिथि तय की थी. उस दिन जीव विज्ञान के लिए 12 व गणित के लिए 10 आवेदकों ने हिस्सा लिया. 1995 में तत्कालीन विद्यालय सेवा

सरकार की अनुमति से पांच अगस्त की तिथि निर्धारित की गयी थी. जिन लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया उसके संबंध में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है. इस मामले में पटना हाइकोर्ट को पुरी स्थिति से अवगत करा दिया गया है. कोर्ट के निर्देश पर ही आगे की कार्यवाही होगी.

राम बुझावन चौधरी, निदेशक, मा शिक्षा विभाग

आयोग के विज्ञापन संख्या 1/85 के माध्यम से जीव विज्ञान में 329 और विज्ञान व गणित में 312 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है. कोर्ट में लंबित मामलों के कारण अब तक बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं हो पायी है. फिलहाल जिन आवेदकों ने काउंसेलिंग में हिस्सा लिया, उनकी नियुक्ति की कार्यवाही चल रही है.

मेडिकल कॉलेजों में बढ़ीं सीटें बरकरार रखने की चुनौती

■ पहले से ही थीं कई कमियां, सीटें बढ़ने से बढ़ा गैप ■ अगले सत्र तक बढ़ानी होंगी सुविधाएं ■ असेसमेंट के लिए बनी टीम

संवाददाता ■ पटना

मेडिकल कॉलेज व निरीक्षक दलों की सूची

कॉलेज	निरीक्षक
पीएमसीएच, पटना	डॉ प्रभात कुमार (एनएमसीएच)
एनएमसीएच, पटना	डॉ अशोक वात्सायन (एनएमसीएच)
एएनएमसीएच, गया	डॉ खुशींद आलम (पीएमसीएच)
डीएमसीएच, दरभंगा	डॉ आरवीएन सिंह (पीएमसीएच)
एसकेएमसीएच, मुजफ्फरपुर	डॉ एचएम झा (डीएमसीएच)
जेएलएनएमसीएच, भागलपुर	डॉ सी राय (डीएमसीएच)
	डॉ कमलेश तिवारी (एसकेएमसीएच)
	डॉ विकास कुमार (एसकेएमसीएच)
	डॉ एम्पन तिवारी (जेएलएनएमसीएच)
	डॉ आरके सिन्हा (जेएलएनएमसीएच)
	डॉ आरवी सिंह (एएनएमसीएच)
	डॉ परवेज अख्तर (एएनएमसीएच)

एम्सीआइ ने राज्य के पुराने मेडिकल कॉलेज-अस्पतालों में इसी सत्र से एमबीबीएस की 50-50 अतिरिक्त सीटों पर नामांकन की अनुमति दे दी है. इन कॉलेजों में पहले से ही शैक्षणिक मापदंड पूरा नहीं था. अतिरिक्त सीटें मिलने के बाद गैप और बढ़ गया है. हर कॉलेज में 50 छात्रों के लिए शिक्षकों के पदों का सुजन करना होगा. लैब व कक्षा में सीटें, पुस्तकालय में पुस्तकें व जर्नल और छात्रावास की सुविधाएं बढ़ानी होंगी. अगर सरकार ने सुविधाएं और शिक्षकों की संख्या नहीं बढ़ायी, तो एम्सीआइ सीटों की संख्या घटा देगी या मान्यता नहीं देगी.

क्षमता आकलन की तैयारी : मुख्य सचिव द्वारा एम्सीआइ को दी गयी अंडरटैकिंग

मिली है. इसके लिए काउंसिल की ओर से किसी तरह की शर्त नहीं लगायी गयी है. बस

पीएमसीएच व एसकेएमसीएच बने मॉडल

पटना ■ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) ने राज्य के दो नये मेडिकल कॉलेजों में 100-100 एमबीबीएस सीटों पर नामांकन की अनुमति इसी सत्र से दी है. नये मेडिकल कॉलेज होने के नते नामांकन से लेकर शैक्षणिक सत्र में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए पीएमसीएच व एसकेएमसीएच को मॉडल कॉलेज के रूप में घोषित किया गया है. स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार ने बताया कि राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, बेतिया के लिए श्रीकुण्ड मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर मेटेर कॉलेज का काम करेगा. इधर, वर्धमान आर्युर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी के लिए पीएचसीएच को मॉडल घोषित किया गया है. दोनों मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में नामांकन शुरू होवाला है. शैक्षणिक सत्र में परेशानी न हो, इसके लिए पीएमसीएच व एसकेएमसीएच हर तरह की मदद करेंगे.

यह निर्देश है कि आगामी सत्र तक आवेदक

यह निर्देश है कि आगामी सत्र तक आवेदक मापदंडों को पूरा कर लिया जाना चाहिए. इसी

आधार पर आगामी सत्र के लिए नामांकन की अनुमति दी जायेगी. अब स्वास्थ्य विभाग सभी पुराने मेडिकल कॉलेजों की क्षमता का आकलन करने की तैयारी में है. विभाग को ओर से छह मेडिकल कॉलेजों के आंतरिक असेसमेंट के लिए 12 चिकित्सकों की टीम गठित की गयी है. एक मेडिकल कॉलेज का असेसमेंट दो चिकित्सक करेंगे. सभी चिकित्सक एम्सीआइ के इम्पेक्टर रह चुके हैं. विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार ने बताया कि एम्सीआइ के पूर्व इम्पेक्टरों को ही रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेवारी दी गयी है. उन्हें कहा गया है कि जिस फॉर्मट में एम्सीआइ द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसी मापदंडों पर रिपोर्ट तैयार की जाये. यह रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध करायी जाये. रिपोर्ट मिलने पर यह आकलन कराना आसान हो जायेगा कि किस मेडिकल कॉलेज की क्षमता क्या है.